

अजीब सा लगा, जब गहलोत व पायलट एक ही मंच पर, गले मिलते, हँसते, गल-बहियां होते नज़र आए

मौका था, कांग्रेस ओबीसी काउंसिल की बैठक का, जो राहुल गांधी ने आहूत की थी

-रेणु मिश्र-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 अप्रैल। राजस्थान कांग्रेस के दो ओबीसी नेता, जो आमतौर पर एक-दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाते हैं और एक-दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, हाल ही में हाथ मिलाते, साथ में हँसते और परस्पर समर्थन, प्रेम तथा एकता का संदेश देते हुए देखे गए।

चरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने तस्वीरें खींच रहे फोटोग्राफरों से कहा कि वे इन तस्वीरों को क्लिक करें और सुरक्षित रखें। दूसरे नेता सचिन पायलट थे। दोनों इंद्रिया भवन में राहुल गांधी द्वारा बुलाई गई कांग्रेस ओबीसी परिषद की बैठक में उपस्थित थे। दिलचस्प बात यह रही कि राहुल गांधी ने चर्चा की शुरुआत विभिन्न

- राहुल गांधी का मैसेज था कि देश के व राज्यों के ओबीसी नेता मिलकर बैठें तथा ओबीसी के मुद्दों पर एक सर्वमान्य राय बनाएं, जिससे यह उभर कर सामने आए कि ओबीसी के कौन से मुद्दे, राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जा सकते हैं।
- राहुल ने इसी संदर्भ में आगे कहा कि अब तक उनके पास नेता अपनी व्यक्तिगत परेशानियों लेकर आते थे, यह रूकना चाहिए तथा इन नेताओं को तय करना चाहिए, मिल बैठकर, कि कौन से मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर उठाने चाहिए, कि मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- शायद राहुल की इस सोच की अनुपालना में गहलोत और पायलट के प्रेम पूर्वक मिलाप का अद्भुत दृश्य देखने को मिला।

राज्यों और देशभर से आए ओबीसी नेताओं से यह कहकर की कि वे एकजुट हों, साथ आएँ, महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाएँ, जिन मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की जरूरत है उन्हें तय करें, और फिर सहमति वाले मुद्दों के साथ उनके पास आएँ, ताकि वे उन्हें पार्टी के भीतर और अन्य मंचों पर उठा

सकें। राहुल गांधी ने कहा कि नेता उनके पास व्यक्तिगत रूप से अपने-अपने मुद्दों के साथ आते हैं, लेकिन अब यह बंद होना चाहिए और उन्हें उन अहम मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने उपस्थित ओबीसी

नेताओं से यह भी कहा कि सरकार उनकी जातिगत जनगणना की मांग मान चुकी है, और यह कार्य यह सुनिश्चित करने के लिए होना ही चाहिए कि ओबीसी, दलित और अन्य वर्गों को सत्ता संरचना में उनका उचित हिस्सा मिल सके, जिसकी वे मांग कर रहे हैं।

आईआरएस अफसर की बेटी की रेप के बाद हत्या

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में बुधवार सुबह एक सीनियर आईआरएस अफसर के घर में उनकी 22 साल की बेटी की रेप के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, घटना सुबह करीब 6 बजे हुई। युवती घर में अकेली थी।

आईआरएस अफसर और उनकी पत्नी रोज की तरह ज़िम गए हुए थे। वापस लौटते तो बेटी का शव कमरे में मिला। वह यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। शुरुआती जांच के अनुसार,

- पुलिस ने आरोपी राहुल मीणा को एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। वह उक्त अफसर के घर में नौकर था।

उसके साथ पहले रेप किया गया। फिर मोबाइल चार्जर के तार से गला घोटकर हत्या की गई।

घटना के करीब 14 घंटे बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी, 19 साल के राहुल मीणा को गिरफ्तार किया। वह द्वारका इलाके के एक होटल में छिपा हुआ था। वह आईआरएस अफसर के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या ममता बनर्जी बौखला गई हैं चुनाव की टैंशन के कारण

एक के बाद एक इतनी अजीबोगरीब टिप्पणियाँ कर रही हैं, अब जनता ने इन पर ध्यान देना ही बंद कर दिया है

-अंजन राय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 अप्रैल। राज्य विधानसभा चुनावों की पूर्व संख्या पर, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से एक और कड़ी फटकार मिली।

सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के व्यवहार पर बेहद कड़ी टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने राज्य की मुख्यमंत्री को उस स्थान पर जाने के लिए फटकार लगाई, जहां ईडी कोयला चोरी और विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच के सिलसिले में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई कर रहा था।

बताया गया कि मुख्यमंत्री जबर्न वहाँ पहुंचीं और ईडी द्वारा जब्त किए गए दस्तावेज अपने साथ ले गईं। वे राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ ईडी की कार्रवाई के बीच पहुंचीं और एजेंसी

■ उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा, जलियाँवाला काण्ड के बाद, इस खौफनाक लोमहर्षक घटना के बारे में महात्मा गांधी ने एक भावभीनी कविता लिखी थी, पर यह सर्वविदित है, जिस कविता का ममता जी उल्लेख कर रही हैं, रविन्द्र नाथ टैगोर ने लिखी थी, नोबल पुरस्कार मिलने के बाद।

■ यहाँ तक कि जब ममता जी ने ईडी के छापे के दौरान, घटना स्थल पर पहुँचकर, ईडी द्वारा जब्त कागज़ात व फाइलें, अपने पुलिस के जत्थे की मदद से जोर जबरदस्ती से उठा लाईं थी तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब यह मामला पहुँचा ममता जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बड़े-बड़े वकील पैरवी कर रहे थे।

की आलोचना करते हुए आधिकारिक फाइलें लेकर वहाँ से चली गईं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार का व्यवहार भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है और यह न्याय, निष्पक्षता तथा कार्यपालिका की संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प.बंगाल की 84 एससी/एसटी बहुल सीटें तय करेगी, किसकी सरकार बनेगी

ये सीटें जंगल महल बैल्ट, उत्तरी बंगाल और दक्षिण बंगाल की मातुआ बैल्ट में फैली हैं

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 अप्रैल। चूँकि बंगाल में गुरुवार को पहले चरण का मतदान शुरू होता है, इसलिए सभी की नज़रें जंगलमहल क्षेत्र, उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल की 'मातुआ बैल्ट' (जिसमें नदिया और उत्तर 24 परगना जैसे जिले शामिल हैं) में फैली 84 अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) सीटों के मतदान स्थानों पर टिकी है।

इन सीटों पर जो भी पार्टी बड़त हासिल करेगी, उसके सरकार बनाने की संभावना अधिक होगी। इन क्षेत्रों में चुनावी मुक़ाबले को और महत्वपूर्ण बनाने वाली बात यह है कि पिछले कुछ चुनावों में मतदाताओं की बदलती निष्ठाएँ साफ तौर पर दिखाई दी हैं। ये सीटें, जो कभी वाम मोर्चा का अभेद्य गढ़ मानी जाती थी, अब बंगाल की

■ वर्ष 2006 तक इस क्षेत्र में वाम मोर्चा का दबदबा था तब इसने यहाँ कि 84 सीटों में से 72 सीटें जीती थीं, पर, 2011 में ममता बनर्जी ने वाम मोर्चा से यह गढ़ छीन लिया। 2016 में भी ममता बनर्जी ने 84 में से 66 सीटें जीती थीं।

■ लेकिन 2021 के गत विधानसभा चुनावों में भाजपा ने इस क्षेत्र में दबदबा बढ़ाया और 84 में से 39 सीटें जीतीं और तृणमूल (36 सीटें) से बराबरी पर रही। इस बार भाजपा व तृणमूल दोनों पूरा जोर लगा रही हैं कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते।

राजनीति का सर्वाधिक अप्रत्याशित रणक्षेत्र बन गई है। 2006 में वाम मोर्चा ने इन 84 में से 72 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2011 के चुनावों में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की परिवर्तन लहर के बीच उसका पूरी तरह सफाया हो गया। इसके

बाद 2016 के चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने 84 में से 66 सीटें (50 एससी और 16 एसटी) जीतीं। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय पैठ बनाई, तथा उसने 32 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चुनाव आयोग ने खड़गे को नोटिस दिया

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कथित तौर पर 'आतंकवादी' कहे जाने के विषय को गंभीरता से लेते हुए उन्हें नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया है।

चुनाव आयोग के अधिकारी सूत्रों ने आज इसकी जानकारी दी। तमिलनाडु

■ खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री को 'आतंकवादी' कहने को आयोग ने गंभीरता से लिया।

में संवाददाता सम्मेलन में खड़गे ने प्रधानमंत्री को कथित तौर पर 'आतंकवादी' कहा था। भारतीय जनता पार्टी ने मामले को गंभीर बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष की प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी की तीखी आलोचना की थी। इस मुद्दे पर भाजपा का प्रतिनिधिमंडल केन्द्रीय मंत्री किरण रिज्जू के नेतृत्व में आज चुनाव आयोग से मिला था। दूसरी ओर, कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पर सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री को आतंकवादी नहीं कहा, बल्कि उनका अर्थ था कि वे राजनेताओं को डरा रहे हैं।

बंगाल चुनाव में मोटरसाइकिल चलाने पर लगा प्रतिबंध

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए जो "अभूतपूर्व" प्रतिबंध लगाए हैं, उनमें बाइक पर प्रतिबंध को "सबसे ज्यादा अभूतपूर्व" माना जा रहा है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 अप्रैल। पश्चिम बंगाल में होने वाले दो चरणों के चुनाव के मद्देनज़र मोटरसाइकिलों के उपयोग पर एक अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाया गया है। चुनाव आयोग ने मतदान से 48 घंटे पहले मोटरसाइकिल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी, यहाँ 23 अप्रैल को मतदान है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक वही, मोटर साइकिल चला सकेंगे, जिन्हें अति आवश्यक काम है। आवाजाही प्रतिबन्धित कर दी है, सिवाय "आपातकालीन" और पारिवारिक ज़रूरतों के। साथ ही, मोटरसाइकिल रैलियों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है।

आयोग के बयान में कहा गया है, "मतदान दिवस से दूसरे दिन तक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान के उद्देश्य से और अन्य आवश्यक

■ आयोग ने मतदान के दो दिन पहले से मतदान के अगले दिन तक के लिए बाइक चलाने और पीछे सवारी बिठाने पर रोक लगाई है, केवल आपात स्थिति में ही इसमें छूट दी जा सकती है पर इसके लिए पुलिस थाने में सूचित कर अनुमति लेनी होगी।

■ आयोग के इस फैसले की भारी आलोचना हो रही है, खासकर गिग वर्कर्स और रैपिडो आदि में बाइक चलाने वालों की तरफ से। उनका कहना है इससे उनके लिए रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जाएगा।

(पिलियन राइडिंग) यात्रा की अनुमति नहीं होगी, सिवाय चिकित्सा आपातकाल, पारिवारिक कार्यक्रम आदि के लिए अनुमति दी जाएगी।" चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी प्रकार की छूट के लिए लोग पहले से स्थानीय पुलिस के पास आवेदन कर सकते हैं।

बाद में आयोग ने स्पष्ट किया कि उचित पहचान पत्र सहित दफ्तर जाने वाले लोगों को भी छूट दी जाएगी।

लिपुलेख दर्ा से भारत-चीन व्यापार जून में शुरू होगा

पिथौरागढ़, 22 अप्रैल। लिपुलेख दर्रा के माध्यम से भारत-चीन सीमा व्यापार वर्ष 2026 के जून के प्रथम सप्ताह से शुरू होकर सितंबर तक चलेगा। भारत-चीन सीमा व्यापार को वर्ष 2026 में पुनः शुरू करने की तैयारियों को लेकर

■ करीब 6 साल के बाद यहाँ से व्यापार शुरू करने की विदेश मंत्रालय ने स्वीकृति दी।

बुधवार को जिलाधिकारी आशीष भटगार्गी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय से लिपुलेख दर्रे के माध्यम से व्यापार शुरू करने की अनापत्ति मिलने के बाद प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। करीब छह वर्षों के अंतराल के बाद फिर से शुरू हो रहे इस सीमा व्यापार को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है और सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ट्रंप ने ईरान के साथ अनिश्चितकाल तक सीज़फायर बढ़ाने का श्रेय पाकिस्तान को दिया

अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साफ-साफ लिख पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर और पाक प्र.मंत्री शहबाज़ शरीफ के अनुरोध पर वे अनिश्चितकाल के लिए सीज़फायर बढ़ा रहे हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 अप्रैल। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अमेरिका-ईरान युद्धविराम समाप्त होने से कुछ घंटे पहले ही इसे अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया, और इसके लिए पाकिस्तान के निवेदन का हवाला दिया। अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि वे गंभीर रूप से विभाजित ईरानी शासन को स्थायी शांति समझौते के लिए एकीकृत प्रस्ताव तैयार करने का समय देना चाहते हैं। यह पहली बार है, जब अमेरिका ने तेहरान की अगली कार्रवाई के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की है, और ट्रंप ने अपनी रणनीति में बदलाव का श्रेय पाकिस्तान ने तृत्व के साथ हुई बातचीत को दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर लिखा, इस तथ्य के

■ ट्रंप ने कहा कि ईरान की सरकार में भारी मुद्रा के रूप से विभाजित है, जो अप्रत्याशित नहीं है, और पाकिस्तान के फौज मार्शल आसिम मुनीर तथा प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ के अनुरोध पर, हमने ईरान पर अपने हमले तब तक रोकने के लिए कहा है, जब तक उनके नेता और प्रतिनिधि कोई एकीकृत प्रस्ताव लेकर नहीं आते।

लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में ईरान के तट पर बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रहेगी, ट्रंप ने कहा, जबकि अमेरिकी सेना "अन्य सभी मामलों में तैयार और सक्षम" रहेगी। उन्होंने कहा कि युद्धविराम "तब तक बढ़ाया जाएगा, जब तक उनका प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हो जाता और उस पर चर्चा पूरी नहीं हो जाती, किसी भी तरह से।"

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बाद में युद्धविराम बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार करने और उसके "कूटनीतिक प्रयासों" पर "विश्वास और भरोसा" दिखाने के लिए ट्रंप का धन्यवाद किया।

■ विशेषज्ञों का कहना है कि पहले ईरान के नेताओं ने शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान का आभार जताया था और अमेरिका भी पाकिस्तान को श्रेय दे रहा है, इससे अंतरराष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान की कूटनीतिक ताकत बढ़ेगी।

■ उपवाद और कमज़ोर अर्थव्यवस्था के कारण दुनिया भर में समस्याग्रस्त राष्ट्र के रूप में देखा जाने वाला देश पाकिस्तान अब अचानक सुर्खियों में आ गया है। पर, मध्यस्थ की यह भूमिका कांटों का ताज है। अगर शांति वार्ता विफल रही तो इसका प्रभाव पाकिस्तान को भी झेलना होगा।

उन्होंने एक्स पर लिखा, मेरी ओर से और फौज मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ओर से, मैं राष्ट्रपति ट्रंप का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए

युद्धविराम बढ़ाया, ताकि चल रहे कूटनीतिक प्रयास आगे बढ़ सकें। पाकिस्तान इस विश्वास और भरोसे के साथ अपने प्रयास जारी रखेगा बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सके।"

उन्होंने आगे कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष युद्धविराम का पालन करेंगे और इस्लामाबाद में निर्धारित दूसरे दौर की वार्ता के दौरान एक व्यापक "शांति समझौते" पर पहुँच सकेंगे, जिससे संघर्ष का स्थायी अंत हो सके। यदि इस्लामाबाद वास्तव में ट्रंप को ईरान पर आगे के हमलों को रोकने के लिए प्रभावित कर पाया है, तो इससे उसकी कूटनीतिक स्थिति को बढ़ा बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक स्तर पर उसकी साख मजबूत होगी। इससे पहले, ईरानी नेताओं ने भी कई मौकों पर पाकिस्तान के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया था। ईरान और अमेरिका के बीच मतभेदों को कम करने के लिए पाकिस्तान के तेज़ प्रयासों के पीछे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

संजय झा फिर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने

पटना, 22 अप्रैल। बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किए

■ पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सांसद आलोक कुमार सुपुन को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

गए हैं। इस फेरबदल को आगामी चुनावों के मद्देनज़र महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जदयू की नई टीम में संजय झा को एक बार फिर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, जहानाबाद के पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। गोपालगंज से सांसद आलोक कुमार सुपुन को पार्टी का राष्ट्रीय (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अंतरराज्यीय ट्रैक्टर तस्करी सिंडिकेट का सरगना सीआईडी के हथ्थे चढ़ा

आरोपी पिछले 12 साल से फरार है, उस पर 50 हजार रु. का इनाम घोषित है

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। सीआईडी (सीबी) पुलिस मुख्यालय की स्पेशल टीम ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 वर्षों से फरार चल रहे 50 हजार रुपए के इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी अंतरराज्यीय ट्रैक्टर वाहन तस्करी सिंडिकेट का सरगना बताया जा रहा है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर गिराव के अन्य सदस्यों और नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है।



आरोपी आबिद मेवाती

थाना बरसाना, जिला मथुरा को वहीं से दस्तयाब किया गया। महानिरीक्षक पुलिस परम ज्योति के सुपरविजन में उपनिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार के नेतृत्व में गठित टीम को सूचना मिली कि आरोपी मथुरा में एक

■ बताया जा रहा है कि आरोपी वर्ष 2012 से इस अवैध कारोबार में सक्रिय था और अब तक 1500 से 2000 से अधिक ट्रैक्टरों की अवैध बिक्री कर चुका है। प्रत्येक वाहन पर करीब 2 लाख रुपए तक का मुनाफा कमाया जाता था।

शुद्धी समारोह में शामिल होने आने वाला है। इस पर टीम ने स्थानीय पुलिस और बूंदी पुलिस को मदद से कुसुम वाटिका में घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। अतिरिक्त महानिरीक्षक (अपराध) विपिन कुमार पाण्डेय ने बताया कि कार्रवाई के दौरान उग्र भीड़ ने आरोपी को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन टीम ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए आरोपी को सुरक्षित हिरासत में लेकर पुलिस थाना हाईवे, मथुरा पहुंचाया, जहां से उसे बूंदी पुलिस को सुपुर्द किया गया। जॉर्ज में सामने आया कि आरोपी अपने गिरोह के साथ मिलकर अलग-अलग राज्यों में ट्रैक्टर लोन पर खरीदता था, फिर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें टों में लोड कर उत्तर प्रदेश के छाता क्षेत्र में भेज देता था। वहां इन वाहनों की अवैध खरीद-फरोख्त कर भारी मुनाफा कमाया जाता था। बताया जा रहा है कि आरोपी वर्ष 2012 से इस अवैध कारोबार में सक्रिय था और अब तक 1500 से 2000 से अधिक ट्रैक्टरों

की अवैध बिक्री कर चुका है। प्रत्येक वाहन पर करीब 2 लाख रुपए तक का मुनाफा कमाया जाता था। आरोपी के खिलाफ राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और हरियाणा में हत्या के प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट और धोखाधड़ी सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से फरार चल रहा था और लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न था। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार के नेतृत्व में हेड कॉन्स्टेबल बृजेश कुमार, करणी सिंह, रविन्द्र सिंह, कृष्णगोपाल, अरुण कुमार, कुलदीप और कॉन्स्टेबल नरेश कुमार की विशेष भूमिका रही। साथ ही एसआई शंकर दयाल शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मियों का तकनीकी सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा।

सीएचओ भर्ती-2020 पेपर लीक का आरोपी जालौर से गिरफ्तार

जयपुर। राजस्थान में संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) भर्ती परीक्षा-2020 के पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने इस संगठित गिरोह के सक्रिय सदस्य गणपत लाल मालवाड़ा (31) निवासी जालौर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुख्य सूत्रधार भूपेन्द्र सारण का करीबी सहयोगी रहा है और पेपर लीक की साक्षिण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है।



आरोपी गणपतलाल मालवाड़ा

■ एसओजी इस मामले में 20 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है

मीणा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। गणपत लाल इस मामले में गिरफ्तार होने वाला 21वां आरोपी है। पूछताछ में सामने आया है कि गणपत लाल ने न केवल भूपेन्द्र सारण को सहयोग किया, बल्कि पेपर लीक के माध्यम से अभ्यर्थियों को संगठित रूप से एकत्रित करने और उन्हें लाभ पहुंचाने में भी शामिल रहा। एसओजी अब आरोपी से इस गिरोह के अन्य नेटवर्क और वित्तीय लेन-देन के बारे में गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि गणपत से पूछताछ में भर्ती परीक्षाओं में सक्रिय अन्य लोगों के बारे में भी महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं।

अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि 10 नवंबर 2020 को आयोजित हुई सीएचओ भर्ती परीक्षा के दौरान जयपुर के निवासी रोड स्थित जगृति विद्या मंदिर सीनियर सेकेंड्री स्कूल को केंद्र बनाया गया था। जांच में सामने आया कि गिरोह ने स्कूल के स्ट्रोंग रूम से अप्रयुक्त प्रश्न-पत्रों की सील खोलकर पेपर लीक किया था। परीक्षा से मात्र दो घंटे पहले प्रश्न-पत्र हथिल कर उसे साँलवर टीम से हल करवाया गया और फिर अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया गया। इस मामले में एसओजी अब तक कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें स्कूल संचालक धीरज शर्मा, मुकेश बाना, बलवीर सुपडा, दिनेश विश्वास, भूपेन्द्र सारण और शेर सिंह

कांग्रेस ने रिफाइनरी में कई घोटाले किए : मुख्यमंत्री

चूरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने देशहित से जुड़े हर मुद्दे का विरोध किया है। इनके नेता महिला आरक्षण का विरोध और सेना का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम से महिलाओं को आरक्षण मिले, इनका काम ही विरोध करना है। उन्होंने कहा कि धारा 370 का कांग्रेस ने विरोध किया। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के लोग वे ही हैं, जो शेखावाटी के लिए हमेशा यमुना के जल का सपना दिखाते थे। चुनाव आते थे तब झूठ के पुल बनाते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने रिफाइनरी में कई तरह के घोटाले और जमीनों के घोटाले किये। इनमें कांग्रेस के लोग कैसे काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इनका हिसाब लेना चाहिए।

जवाहर सर्किल के पास 13 बीघा भूमि मामले में जेडीए की अपील मंजूर

राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर एयरपोर्ट विस्तार के लिए 51 वर्ष पहले अवाप्त जमीन के मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण को राहत दी

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर एयरपोर्ट विस्तार के लिए 51 वर्ष पहले अवाप्त जमीन के मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण को राहत दी है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अवाप्तशुदा जमीन के बदले 25 प्रतिशत जमीन देने के फैसले के बाद ही जमीन देने का आदेश दिया, उसमें अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा कोर्ट में जमा कराया जा चुका है और उस जमीन पर 2017 में कब्जा लेकर फॉर्मिड करार दिया। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश जेडीए की अपील को मंजूर करते हुए दिए।

■ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के द्वारा दिए गए आदेश को खारिज किया

जेडीए की ओर से अपील में अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जिस मामले में जमीन के बदले 25 प्रतिशत विकसित

से पहले की है, इसलिए एकलपीठ का आदेश सही है। न काश्तकारों को मुआवजा मिला है और न ही कब्जा लिया गया है। इस मामले में अवाप्तशुदा जमीन के बदले 25 प्रतिशत विकसित जमीन देने की राज्य सरकार की गारंटीवादी लागू होती है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने जेडीए की अपील को मंजूर करते हुए एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। मामले के अनुसार अवाप्त को काश्तकारों ने वर्ष 1974 में याचिका के जरिए चुनौती दी, जिसे हाईकोर्ट ने मई 1975 में खारिज कर दिया। साल 1975 में फिर याचिका दायर की गई, जो मार्च 1978 में निस्तारित कर दी गई।

बी.सी.आर. चुनाव में अव्यवस्था के बाद हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट पोलिंग बूथ का मतदान रद्द

इन दोनों जगहों पर जल्द ही नई चुनाव तिथि घोषित की जाएगी

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। प्रदेश के अधिवक्ताओं की नियामक संस्था बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के 23 सदस्यों के चुनाव बुधवार को प्रेक्षाभूमि में आयोजित हुए। हालांकि इस दौरान जयपुर में हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट में पोलिंग बूथ पर हुई अव्यवस्था और पारदर्शिता के अभाव के चलते मतदान प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। यहां जल्दी ही नई चुनाव तिथि घोषित की जाएगी। हाईकोर्ट जयपुर के पोलिंग ऑफिसर अधिवक्ता बंसत सिंह छावा ने बताया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा था और इसमें अव्यवस्था सामने आ रही थी। इन कारणों से ही हाईकोर्ट में बीसीआर चुनाव रद्द किया गया है। हाईकोर्ट प्रदेशभर में बीसीआर चुनाव



बार कौंसिल के चुनाव में बुधवार को अव्यवस्था के बाद अधिवक्ताओं ने हंगामा कर दिया।

मतदान निरस्त करने का निर्णय लिया। सेशन कोर्ट में मतदानों की संख्या 5439 है और यहाँ पर भी बागू के 57 मतों के लिए भी मतदान होना था। हाईकोर्ट बूथ पर मतदान करीब 50 मिनट देरी से शुरू हुआ और हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस वीएस दवे ने पहला मत दिया, लेकिन इसके बाद ही मतदान प्रक्रिया में अव्यवस्था होना और पारदर्शिता नहीं होने के कारण चुनाव को रद्द कर दिया। चुनाव सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस सुधांशु धूलिया की निगरानी में हो रहे हैं और राजस्थान में चुनाव कराने की जिम्मेदारी दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जे आर मिश्रा की तीन सदस्यीय कमेटी के पास है। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस मनोज गर्ग राज्य स्तरीय ऑनैवर बनाए गए हैं।

कार सवसे बड़ा पोलिंग बूथ है और यहां पर 14 हजार 781 मतदाता हैं। वहीं बनीपार्क स्थित सेशन कोर्ट में भी चुनाव मतदान की सही व्यवस्था नहीं होने, फर्जी मतदान के आरोप सहित अव्यवस्था व अनियमितता के चलते

कटार के साथ बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। सिंधी कैप पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक शातिर बदमाश को दबोचा है, जिसके कब्जे से एक अवैध धारदार कटार बरामद की गई है। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) प्रशांत किरण ने बताया कि शहर में अवैध हथियारों की रोकथाम और अपराधियों को धरपकड़ के लिए सभी थानाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार गुप्ता और सहायक पुलिस आयुक्त (सदर) धर्मवीर सिंह के सुपरविजन में पुलिस टीम इलाके में गश्त कर रही थी। थानाधिकारी माधोसिंह के नेतृत्व में टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मोहसिन (23) को गिरफ्तार किया। आरोपी भट्टा बस्ती के शहीद इंदिरा ज्योति नगर का निवासी है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध धारदार कटार मिली, जिसे पुलिस ने तुरंत जब््त कर लिया।

एआई से बना रहे थे न्यूज चैनल का फर्जी वीडियो

जयपुर पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश कर चार आरोपियों को दबोचा

जयपुर। तकनीकी के दुरुपयोग से समाज में भ्रम फैलाने वाली के खिलाफ जयपुर साइबर पुलिस ने बड़ी सफलता हांसी है। पुलिस ने न्यूज चैनल के लोगों और एंकर की आवाज का इस्तेमाल कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित फर्जी वीडियो बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि 18 अप्रैल को परिवाराई सत्यनारायण शर्मा ने मामला दर्ज कराया था कि फेसबुक पर एक एआई जनित वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें न्यूज चैनल के एडिटर बैकग्राउंड और एंकर की आवाज को एडिटर का श्रव्य जानकारी परोसी गई थी। लोग इसे सच मानकर धड़ल्ले से शेयर कर रहे थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएफएस और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर डॉ. अजय सिंह और पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) राजेश राज के सुपरविजन में गठित विशेष टीम ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर फर्जी वीडियो के मूल स्रोत को पहचाना था। पुलिस ने दक्षिण देकर इस साक्षिण में शामिल चार मुख्य किरदार बिलाल खान (27) निवासी भोपाल मध्य प्रदेश, इनाम अहमद (29) निवासी भोपाल मध्य प्रदेश, निखिल प्रजापत (22) निवासी भोपाल मध्य प्रदेश और अमृता धुमाल (37) निवासी पंजाब को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने हाई-टेक, एआई टूल्स का उपयोग कर न्यूज क्लिप को एडिट किया। उन्होंने एंकर को आवाज की क्लोन किया और सुनिश्चित तरीके से इसे सोशल मीडिया पर वायरल कराया। पुलिस की तकनीकी टीम यह यह पता लगा रही है कि इस वीडियो को बनाने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था और क्या इसमें कोई बड़ा वित्तीय हित जुड़ा था। इस त्वरित कार्रवाई में साइबर एक्सपर्ट्स और पुलिस अधिकारियों की टीम शामिल रही, जिसमें थानाधिकारी और तकनीकी सहायकों ने एआई जनित वीडियो के डिजिटल फुटप्रिंट्स का पीछा कर आरोपियों को दबोचने में सफलता हासिल की।

कौशल शिक्षा का उपयोग राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए हो : हरिभाऊ बागड़े

नैतिक मूल्यों की शिक्षा से भौतिक विकास की गुणवत्ता में वृद्धि होती है : राज्यपाल

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि कौशल शिक्षा का उपयोग राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसके पास अच्छा कौशल है, उसे सभी स्थानों पर काम मिलता है, वह कभी भ्रष्टा नहीं रहता। उन्होंने कौशल शिक्षा के साथ विश्वविद्यालयों में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा से भौतिक विकास की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। राज्यपाल बागड़े बुधवार को विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष दीक्षांत समारोह आयोजक रूप से किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह भले ही छोटे स्तर पर ही हो, परंतु नियमित होना चाहिए। जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय में पढ़ते



राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बुधवार को विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। हैं, उन्हें समय पर डिग्री मिलनी चाहिए। इससे उन्हें दिशा मिलती है। बागड़े ने कहा कि प्रतिभाशाली राष्ट्र के लिए कौशल विकास के साथ

विद्यार्थियों को नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के साथ उन्हें नकल करने की प्रवृत्ति से

■ 'अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा को बदल कर गुलाम मानसिकता की शिक्षा प्रदान की'

रोके जाने की शिक्षा दी जाए। उन्होंने इसके लिए शिक्षकों को स्वयं को अपडेट रखते हुए शिक्षा का प्रभावी विकास करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में अच्छा नागरिक बनाने के साथ आदर्श आचरण पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यपाल ने कहा कि आजादी से पहले देश में आठ लाख से अधिक गुरुकुल थे। इनमें सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेजों ने भारत की इस शिक्षा को बदल कर गुलाम मानसिकता की शिक्षा प्रदान की। बागड़े ने विश्वकर्मा को देवताओं के शिल्पकार बताते हुए कहा कि वह ब्रह्मांड के प्रथम इंजीनियर थे। उन्होंने

एम. विश्वेश्वरैया को याद करते हुए उनके अभियांत्रिकी कौशल और समय पाबंदी से सीख लेने का आनंद बताया। उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले एवं खेल विभाग मंत्री कनैल राजेश्वर सिंह राठौड़ ने कहा कि जो कुछ विद्यार्थी सीखे उसका दायरा सीमित नहीं रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को सज्जनात्मक रहने, निरंतर दूसरों से सीखते हुए अपने कौशल से दुनिया को बदलने, विकसित किए जाने का आह्वान किया। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. देवस्वरूप ने सभी का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा कौशल विकास के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। इससे पहले विश्वविद्यालय के बारे में फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। राज्यपाल ने इससे पहले विद्यार्थियों को डिग्री और पदक प्रदान किए।

परशुराम शोभायात्रा को लेकर विशेष व्यवस्था

जयपुर। भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में 23 अप्रैल 2026 को शहर में बौध्द शोभायात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान शहर के प्रमुख क्षेत्र में व्यापक यातायात व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। पुलिस प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शोभायात्रा सायं 6:30 बजे चांदपोल क्षेत्र के जलेब चौक से रवाना होकर हवामहल बाजार, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, बापू बाजार, न्यू गेट, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया गेट और त्रिपोलिया बाजार होते हुए छोटी चौपड़ पहुंचकर विसर्जित होगी। यात्रा के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। शोभायात्रा मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही सायंकाल 4 बजे से सांगानेरी गेट, घाटगेट चौराहा, धोबीघाट, रामगंज मोड़ और संजय सर्किल से मिनी व सिटी बसें का संचालन परकोटा क्षेत्र में बंद रहेगा। हवामहल बाजार, जौहरी बाजार, बापू बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार और गंगोत्री बाजार में भी शाम 4 बजे से सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन और पार्किंग निषेध रहेगी। विभिन्न प्रमुख मार्गों जैसे सुधास चौक, बड़ी चौपड़, रामगंज चौपड़, सांगानेरी गेट और त्रिपोलिया की ओर आने वाले यातायात को डाइवर्ट कर वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा। इसके अलावा न्यू गेट, रामनवास बाग चौराहा, नेहरू बाजार और त्रिपोलिया गेट-पाईंट से चौड़ा रास्ता की ओर किसी भी प्रकार के वाहन नहीं जाने दिए जाएंगे। छोटी चौपड़ और त्रिपोलिया क्षेत्र में भी यातायात प्रतिबंधित रहेगा।

युग पुरुषों की शौर्य गाथाएँ आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने चूरु में "शौर्य के साथ संकल्प दिवस" पर ले.जनरल सगत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया

चूरु/जयपुर, 22 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान वीरों एवं रणबाँकुरों की धरती है। यहां के सपूतों ने अनेक युद्धों में वीरता एवं शौर्य का परिचय दिया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ को नमन करते हुए कहा कि वीर भूमि के इस सपूत ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर साहस का अप्रतिम उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि इन युगपुरुषों से युवाओं को दिशा मिलती है तथा इनकी शौर्य गाथाएँ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का काम करेंगी।

शर्मा बुधवार को चूरु में आयोजित लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की मूर्ति अनावरण एवं 'शौर्य के साथ संकल्प दिवस' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने 19 साल की उम्र में बीकानेर रियासत की सेना में सैन्य जीवन से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पद्म भूषण और परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के सम्मान में चूरु स्टेडियम का नाम सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सैनिक कल्याण के लिए सजग होकर निरन्तर कार्य कर रही है। डीडवना-कुचामन में राजस्थान के पहले एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर की स्थापना की तथा नवीन जिला सैनिक कल्याण



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को चूरु में आयोजित लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ मौजूद थे।

कार्यालय खोले जा रहे हैं। साथ ही, आरटीडीसी के सभी होटलों और गेस्ट हाउसों में वीरगाथाओं को 50 प्रतिशत और सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल की प्रतिमा

अनावरण से नौजवानों को नई दिशा मिलेगी एवं आगामी पीढ़ी इससे प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएगी।

सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर ने लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के बलिदान एवं साहस का जिक्र करते

हुए कहा कि भारत-चीन युद्ध में नाथूला बॉर्डर पर उन्होंने दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने आजाद भारत की सेना में विभिन्न पदों पर अपना कौशल सिद्ध किया। चूरु में जन्मे सिंह का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

■ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर व पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने ले.जनरल सगत सिंह के 1971 के युद्ध में योगदान को याद किया।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह भारत की सैन्य गौरवगाथा के अमर प्रतीक हैं। 1971 के युद्ध में मेघना नदी पार कर उनकी कुशल रणनीति ने पाकिस्तान को पराजित किया और बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार नायक, पैरालिंपिक कमिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेन्द्र झाड़िया, विधायक हरलाल सहायण सहित, विभिन्न जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

क्या ममता बनर्जी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अदालत ने राज्य के वकीलों द्वारा प्रस्तुत कानूनी तर्कों को भी खारिज कर दिया। ईडी अधिकारियों के मौलिक अधिकारों को लेकर दिए गए तर्कों को संक्षेप में खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि कार्यपालिका के हस्तक्षेप की वास्तविकता निर्विवाद है।

मतदान दिवस नजदीक आते ही ममता बनर्जी का मानसिक संतुलन बिगड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है और वे एक के बाद एक गलतियाँ कर रही हैं। उनके चुनावी भाषणों में न तो राजनीतिक सामग्री है और न ही नीतिगत चर्चा वे असंबंधित मुद्दों पर टिप्पणी कर रही हैं।

एक चुनावी सभा में उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार का उल्लेख करते हुए कहा कि इस घटना के जवाब में महात्मा गांधी ने एक कविता लिखी थी, जिसे उन्होंने रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद लिखी गई कविता बताया।

उनकी इस तरह की गलतियाँ लगातार सामने आ रही हैं और लोग अब

■ ममता जी के वकीलों की मजबूत टीम ने यह दलील दी कि ईडी को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इन वकीलों की दलील को दो सैकड़ में अस्वीकार करते हुए कहा। सरकार द्वारा छापे की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का मामला साफ दिख रहा है कहकर ममता जी के खिलाफ सख्त "ऑब्जर्वेशन" किए।

शायद इन पर ध्यान देना भी बंद कर चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यदि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। यदि बड़ी संख्या में तैनात केन्द्रीय बल हिंसा को रोकने में सफल रहते हैं और लोगों को स्वतंत्र रूप से मतदान करने दिया जाता है, तो तुणमूल कांग्रेस के लिए स्थिति कठिन हो सकती है।

लंबे समय से सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, सत्तारूढ़ तंत्र के लोगों द्वारा कथित आपराधिक दबाव और एक सरकारी अस्पताल में एक युवा महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या जैसी घटनाओं ने सरकार के प्रति नकारात्मक माहौल

बनाया है। इसके अलावा, ममता बनर्जी की मुस्लिम मतदाताओं पर पकड़ भी कमजोर पड़ती दिखी है। समुदाय के भीतर से कई आवाजें उनके और उनकी सरकार के खिलाफ उठ रही हैं। इन बदलावों को देखते हुए वे बहुसंख्यक समुदाय की सहानुभूति हासिल करने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करती नजर आ रही हैं।

इस चुनाव के नतीजे काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेंगे कि मुस्लिम वोट कितनी हद तक विभाजित होते हैं। जितना अधिक वोट तुणमूल कांग्रेस से दूर जाएगा, उतना ही अधिक लाभ भाजपा को होगा।

ट्रंप ने ईरान के साथ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उसकी कूटनीतिक स्थिति को पुनः स्थापित करने और निवेश आकर्षित करने की कोशिश है। मिडिल ईस्ट में अस्थिरता पूँजी के संकट से जुड़ रहे इस्लामाबाद के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह न केवल क्षेत्रीय शांति के लिए चुनौती है, बल्कि सऊदी अरब के साथ उसके सुरक्षा समझौते और खाड़ी से ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भरता के कारण उसे संघर्ष में खींच सकती है।

पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (पीआईडीई) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, तेल की बढ़ती कीमतें आयात बिल बढ़ाती हैं, महंगाई का दबाव बढ़ाती हैं और विनियम दर पर दबाव डालती हैं, जिससे आर्थिक गतिविधि धीमी पड़ती है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया, "स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो अभी बंद है, अगर यह बंद लंबे समय तक जारी रहता है, तो औद्योगिक लागत बढ़ा सकता है और समग्र व्यापारिक विश्वास को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा, ऊंची ऊर्जा कीमतें व्यापार घाटा बढ़ा सकती हैं और बाहरी वित्तीय जरूरतों पर दबाव डाल सकती हैं।"

अक्सर धार्मिक उग्रवाद के

आंतरिक खतरों और कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समयाग्रस्त देश के रूप में देखे जाने वाले इस्लामाबाद ने इस संघर्ष में अपनी तटस्थता और दोनों देशों से अच्छे संबंधों का लाभ उठाते हुए "मध्यस्थ" की भूमिका निभाने के मौके को हाथों हाथ लिया। पिछले सप्ताह तेहरान की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इजरायल और लेबनान के बीच युद्धविराम कराने के साथ-साथ

रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने में भी प्रगति की थी, हालांकि यह अल्पकालिक साबित हुआ। कई जगहों पर पाकिस्तान की छवि एक कमजोर अर्थव्यवस्था और आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश की रही है। हालांकि, वह मुस्लिम दुनिया का एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसके पास 6 लाख सैनिकों की सेना है, इस नाते इस्लामाबाद मानता है कि वह अब तक अपनी क्षमता से कम प्रभाव डाल रहा था।

जैसे-जैसे एक नयी बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था आकार ले रही है, पाकिस्तान के नेता अपनी सैन्य ताकत का उपयोग करते हुए अधिक प्रभाव

हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कमजोर अर्थव्यवस्था और अस्थिर राजनीति की कमियों को संतुलित किया जा सके।

हाल के समय में पाकिस्तान की आर्थिक कमजोरी स्पष्ट रही है, जहाँ पैसे बचाने के लिए योजना बिजली कटौती की जा रही है और सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर का आपातकालीन ऋण लिया गया है। वह उम्मीद कर रहा है कि बढ़ती वैश्विक साख से उसे अधिक निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

हालांकि, इसके लिए करों में कमी और मजबूत कानून जैसे आर्थिक सुधार भी जरूरी होंगे। पाकिस्तान पहले ही अमेरिका के साथ कई आर्थिक समझौते कर चुका है। यदि वे वातावरण युद्ध को समाप्त करने में सफल रहती हैं, तो इससे इस्लामाबाद की विश्वसनीयता और बढ़ेगी और नए अवसर खुलेंगे।

लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि यदि बातचीत विफल होती है, तो पाकिस्तान पर भी इसका दबाव आ सकता है। पहले से ही इस्लामाबाद पर अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका का विरोध करते हैं।

आईआरएस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

घर का पुराना नौकर है। उसे करीब एक महीने पहले पैसे में गड़बड़ी के आरोप में काम से निकाला गया था। राहुल मीणा राजस्थान के अलवर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक, वह करीब आठ महीने तक आईआरएस अफसर के घर पर नौकर था। वह आईआरएस अफसर के घर के हर कोने से वाकिफ था। उसे यह भी पता था कि युवती के माता-पिता कब वॉक या जिम के लिए घर से निकलते हैं।

प.बंगाल की 84 एससी/एसटी बहुल सीटें ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एससी और 7 एसटी सीटें जीतीं, जबकि टीएमसी का प्रदर्शन भी लगभग बराबरी पर रहा, क्योंकि पार्टी ने 36 एससी सीटें हासिल कीं।

इस चुनाव में टीएमसी और भाजपा दोनों ही अपने पक्ष में वोटों के रुझान (स्विंग फैक्टर) पर भरोसा कर रही हैं। इन पार्टियों के प्रमुख नेता, जिनमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री

ममता बनर्जी शामिल हैं, ने जंगलमहल क्षेत्र के पुरलिया, बंकुरा, पश्चिम मिदनापुर और झारग्राम जैसे इलाकों में व्यापक प्रचार किया है।

इस चुनाव में एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र उत्तर बंगाल के रूप में उभरा है, जहाँ एससी और एसटी आवादी का मिश्रण है और जिसमें कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी तथा पूर्व और पश्चिम दिनाजपुर जिले शामिल

हैं। बांग्लादेश से सटे दक्षिण बंगाल की एससी-बहुल मातुआ बेल्ट भाजपा के लिए एक खास लक्ष्य रही है, जहाँ वह राजबंशी समुदाय के बीच भी अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं टीएमसी को उम्मीद है कि वह अपने स्थानीय विकास कार्यो और "लक्ष्मी भंडार" जैसी कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर इन 84 सीटों पर अपना प्रभाव बनाए रखेगी।

संजय झा फिर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निशांत कुमार को लगातार पार्टी गतिविधियों में सक्रिय नजर आ रहे हैं। वे पार्टी कार्यालय में बैठकों के साथ-साथ कार्यक्रमों से मुलाकात कर संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि वे अगले महीने बिहार यात्रा पर भी निकल सकते हैं, जिससे जदयू के जनसंपर्क अभियान को और गति मिलने की उम्मीद है।

MARUTI SUZUKI

NEXA

EXPERIENCE GRAND IN EVERY DRIVE WITH THE GRAND VITARA.

NOW AT ₹ 9 999
₹ 8 999 PER MONTH



EFFECTIVE PRICE OF
₹ 9.92 LAKH*

GRAND VITARA



SCAN TO CONNECT TO A SHOWROOM NEAR YOU

T&C available at your nearest dealership. Creative visualization. Images used are for illustration purposes only. For details on safety features (including airbags), refer owner's manual. NEXA dealers exclusively provide all offers, which vary by model and variant. Offers are subject to availability of stock. *Ex. showroom Price of ₹ 10.77 lakh, Consumer Offer (-) ₹ 25,000, Exchange Bonus (-) ₹ 30,000, Loyalty Upgrade Bonus (-) ₹ 10,000 = ₹ 9.92 lakh. The actual effective price mentioned may vary based on the customer's eligibility, profile, and applicable offers at the time of purchase. Offer valid on Grand Vitara Sigma Variant. Maruti Suzuki may withdraw offers without notice. Offer valid till limited period. Features and accessories shown may not be part of the standard fitment. *EMI @ Rs 8 999* is a scheme illustration for upgrade from Brezza to Grand Vitara Sigma variant. Balloon Finance EMI is calculated @ 9.5% rate of interest; Balloon EMI is 30% of the total loan amount and loan tenure of 5 years. Balloon Finance Scheme provided by select financiers.

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, जी-1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौन सिटी, जिला करौली से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2008/27147 जयपुर कार्यालय: सुधाम एम.आई.रोड, जयपुर फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033, बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्या, बीकानेर फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आर्यभट्ट मैन रोड आयड, उदयपुर फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665 जालोर कार्यालय: जी-1/63, इन्स्टीट्यूट परिया, फेस प्रथम, जालोर फोन 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 चूरु कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरु, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908